Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 1 | ISSN : 2581- 6306

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020
## देर आये मगर दुरूस्त आये

**श्रीमती रंजीता गुप्ता**
**एम0एस0सी0, एम0एड्0, एम0फिल्, नेट**
**प्रवक्ता–शिक्षाशास्त्र**
**राजकीय बालिका इण्टर कालेज**
**बिहार, प्रतापगढ़**

**Article Info**

Volume 4, Issue 1

Page Number : 63-78

**Publication Issue :**

January-February-2021

**सारांश** – भारतीय शिक्षा की जीर्ण–शीर्ण इमारत का पुनरूद्धार होने का वह बहुप्रतिक्षित क्षण आज 34 वर्षों के बाद आ ही गया। अंग्रेजों के समय से चली आ रही घिसी–पिटी परिपाटी को तोड़कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा का एक नया ढांचा प्रस्तुत किया है। इसमें नवीनता, मौलिकता के साथ–साथ व्यापकता भी है गरीब छात्र/छात्राओं के प्रति उदारता भी है और उनके भविष्य को संवारने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सपना भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी। रा0शि0नि0 2020 के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉ0 के0 कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में मई 2019 में ''राष्ट्रीय नीति का मसौदा'' प्रस्तुत किया था। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत **बर्थडे गार्डन, ट्राइबल म्यूजियम, भाषण कला, अतिरिक्त कक्षा शिक्षण, वर्चुअल रियेलिटी बॉक्सः स्टॉम्प किट तैयार करना, वाचन, कबाड़ से जुगाड़, विज्ञान किट, मोबाइल शिक्षा, I.C.T. का प्रयोग (Information & Communication Technology), दोस्ती क्लब/मित्रता क्लब के साथ–साथ समानता की भावना पर विशेष जोर दिया गया।** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देर में भले आयी हो लेकिन इसका कार्यक्रम, योजना, कार्यविधि इतनी प्रभावशाली है कि यह पिछली सभी शिक्षा योजनाओं की कमियों को दूर कर देगी। यदि नई शिक्षा योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया तो भारत निश्चित रूप से विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा दिखाई देगा। नई शिक्षा नीति 2020 वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा प्रणाली में सुधार की एक व्यापक, विस्तृत कार्ययोजना है। इस शिक्षा नीति के द्वारा हम छात्रों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का सफल प्रयास कर सकेंगे।

**Article History**

Accepted : 16 Jan 2021

Published : 30 Jan 2021

**की–वर्ड–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

**Copyright:** © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

भारतीय शिक्षा की जीर्ण–शीर्ण इमारत का पुनरूद्धार होने का वह बहुप्रतिक्षित क्षण आज 34 वर्षों के बाद आ ही गया। अंग्रेजों के समय से चली आ रही घिसी–पिटी परिपाटी को तोड़कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा का एक नया ढांचा प्रस्तुत किया है। इसमें नवीनता, मौलिकता के साथ–साथ व्यापकता भी है गरीब छात्र/छात्राओं के प्रति उदारता भी है और उनके भविष्य को संवारने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सपना भी है। शिक्षा के इस नवीन उद्यान में मातृभाषा के आंगन में भारत का भविष्य पुष्पित व पल्लवित होगा और विकास के सर्वांगीण लक्ष्य को निःसंदेह प्राप्त भी करेगा। वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें बाल्यावस्था की नींव को मजबूत करने का आधार प्रदान किया गया है। बाल्यावस्था के विकास को बाल मनोविज्ञान को दृष्टिगत रखते हुए एक नवीन पाठ्यक्रम की रचना का संकल्प लिया गया है। निःसंदेह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। जो भारत को आत्मनिर्भर और विश्व में अग्रणी बनाएगी। शिक्षा के इस नवीन प्रारूप को साकार करने के लिए सरकार ने जी0डी0पी0 का 6 प्रतिशत खर्च करने का फैसला लिया है।

भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 ई0 में इंदिरा गाँधी सरकार में आयी थी और 1986 ई0 में राजीव गाँधी सरकार में दूसरी नीति आयी थी और 1992 में पी0वी0 नरसिम्हाराव सरकार ने इसमें संशोधन कराया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी। रा0शि0नि0 2020 के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉ0 के0 कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में मई 2019 में ‘‘राष्ट्रीय नीति का मसौदा’’ प्रस्तुत किया था।

कक्षा 6 से छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की शुरूआत कोई नयी बात नहीं है अपितु यह राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा या हस्तकला आधारित शिक्षा से ही प्रेरित है इसका संशोधित रूप है। आये दिन स्कूल–कॉलेजों की मनमानी फीस को लेकर अभिभावकगण विरोध करते रहे हैं; किन्तु समस्या हल न हो सकी। अतः नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा स्कूल, कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण रखने के लिए एक तंत्र/प्रणाली को बनाया जा रहा है। जो स्कूल कॉलेजों की फीस को अभिभावकों की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने का कार्य करेगा। जिससे दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जा सके।

वर्तमान में अंग्रेजी के मकड़जाल में फंसी शिक्षा पाली, फारसी, प्राकृत तथा अन्य स्थानीय भाषाओं को भूल चुकी है। ये भाषाएँ जनमानस की भाषा है हमारी गौरवशाली प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं जिसे वर्तमान में जीवंत करने का संकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लिया है। भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए ‘‘भारतीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान’’ (Indian Institute of Translation and Interpretation-I.I.T.I.) को स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से मातृभाषा/स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिये जाने का सुझाव दिया है। इस सत्य से हम सभी परिचित हैं कि अपनी भाषा में पढ़ी/सुनी बातें हमें अधिक समझ में भी आती हैं और याद रहती हैं। कई छात्र सिर्फ इसलिए पढ़ाई में अन्य छात्रों से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको अध्यापक की भाषा ही समझ में नहीं आती। आज भी अधिकांश घरों में स्थानीय भाषा बोली जाती है यदि इसी भाषा में पढ़ाई हो तो पढ़ाई एक बोझ

न रहकर एक मनोरंजक मार्ग बन जायेगी। छात्र विषय को समझने और आत्मसात करने पर ध्यान देंगे। भाषा एक अवरोध न होकर सीखने का सरल मार्ग बन जाएगी। अभिभावक भी घरो में अपने बालकों की पढ़ाई में मदद कर सकेंगे। आजकल हर जगह अंग्रेजी भाषा सिखाने के कोचिंग संस्थान खुल गये हैं। जिन स्कूलों में सभी विषय अंग्रेजी भाषा में पढ़ाये जाते हैं वहां बाल्यावस्था से ही बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग भेजा जाता है। रा0शि0नी0 2020 में त्रिभाषा सूत्र के अनुसार किसी भी छात्र. पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करना छात्रों के लिए एक सुखद अनुभव होगा। इससे शिक्षा व शिक्षण से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसे अनेक देश है (उदाहरणार्थ– फिनलैण्ड, जापान, इजराइल, फ्रांस, चीन, पोलैण्ड, यूएस) जिन्होंने अपनी भाषा को सर्वोच्च स्थान देकर विश्व में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लार्ड मैकाले द्वारा थोपी गई अंग्रेजी भाषा ने हमें आगे बढ़ाने की बजाए पीछे ही धकेला है। इसने हमारे समाज में ऊँच–नीच (अंग्रेजी भाषा जानने वाले और न जानने वाले) की गहरी खाई को खोदा है और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को आत्महीनता के दलदल में धकेल दिया है। जिसके कारण अनेक क्षमतावान, मेधावी छात्र अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं।

शिक्षा के पुरातन ढांचे 10+2 को समाप्त करके रा0शि0नी0 2020 ने स्कूली शिक्षा का एक नवीन ढाँचा प्रस्तुत किया है। यह नवीन शिक्षा प्रणाली अधिक व्यवहारपरक होने के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनाने वाली है। यह नवीन शिक्षा प्रणाली स्वावलंबी भारत की नींव को मजबूत आधार प्रदान करने वाली है।

**<u>नवीन स्कूल शिक्षा प्रणाली 5+3+3+4</u>**

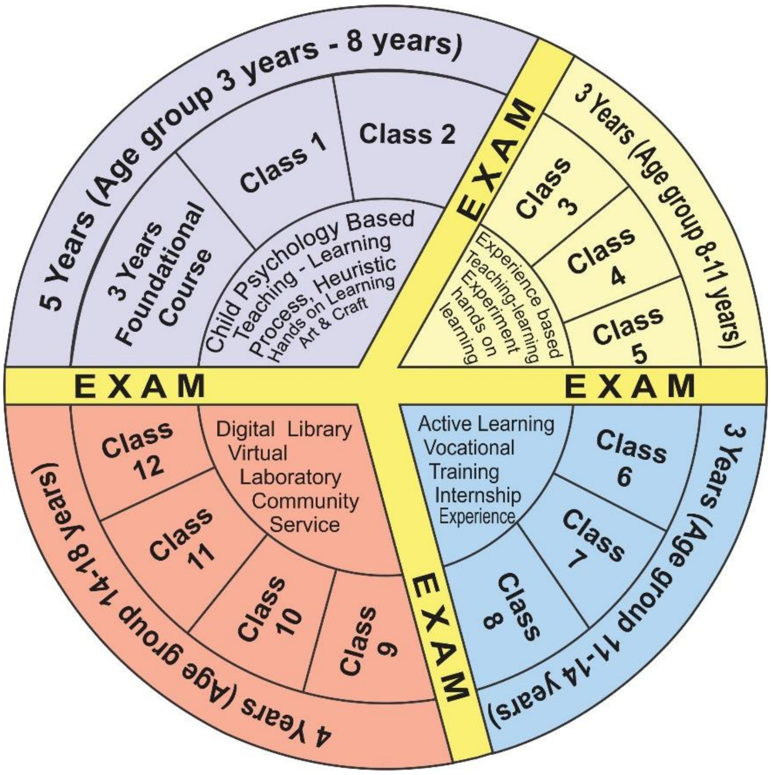

नई शिक्षा नीति में कक्षा 1 से पूर्व 3 वर्ष का फाउंडेशन कोर्स होगा। जिसमें 3 वर्ष के बालक/बालिका का प्रवेश आंगनबाड़ी/बालवाटिका/ प्री–स्कूल में किया जायेगा। इसमें प्रारम्भिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक खास पाठ्यक्रम का निर्माण ''प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा'' (Early Childhood Care and Education E.C.C.E.) कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाएगा। इसका कार्यक्रम वर्तमान में प्रचलित प्ले–स्कूल जैसा ही होगा। जिसमें छात्र खेल–खेल में खिलौनों के माध्यम से, गीत–संगीत द्वारा, स्वक्रिया द्वारा मनोरंजक तरीके से सीखेंगे। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से पढ़ाई करायी जाती है। इसमें प्री–स्कूल, नर्सरी, के0जी0 की पढ़ाई नहीं होती है। प्री–स्कूल व्यवस्था बाल मनोविज्ञान आधारित शिक्षा है जिसे रूसों, पेस्तालॉजी, फ्राबेल तथा मारिया मॉटेसरी ने शुरू किया था। बाल मनोविज्ञान आधारित शिक्षा हमारी निर्जीव, पुस्तकीय, प्राथमिक शिक्षा में नये प्राण फूंक कर उसे जीवंत बना सकती है। इससे प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन बढ़ेगा और अपव्यय और अवरोधन की समस्या का भी समाधान होगा।

कक्षा 6 से बच्चों को प्रोफेशनल स्किल अर्थात व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा भी दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। जिससे छात्र पढ़ाई के साथ–साथ व्यावसायिक कुशलता को प्राप्त करेंगे और स्वरोजगार व स्वावलंबन के मार्ग को चुनेंगे। शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने में यह प्रयोग अवश्य सफल होगा। बेरोजगारी घटने से समाज में व्याप्त अन्य समस्याओं चोरी, डकैती, लूट–पाट, छिनैती, भ्रष्टाचार को दूर करने में सहायता मिलेगा। देश व समाज की उन्नति व्यक्ति की उन्नति पर निर्भर करता है। व्यक्ति का उत्थान ही समाज और देश को विकसित राष्ट्रों के समकक्ष खड़ा होने में आधार प्रदान करेगा।

एक खुशहाल समाज व राष्ट्र तभी संभव है जब देश का हर नागरिक शिक्षित तथा आत्मनिर्भर हो। रा0शि0नी0 2020 की यह योजना देश व समाज को विकास के पथ पर आगे ले जाने वाली साबित होगी। कक्षा 6 से व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ेगा। प्रत्येक छात्र/छात्रा को पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिल पाना असंभव है। न तो इतनी नौकरियाँ है और न उसके लिए पर्याप्त क्षमता व दक्षता (कार्य–कुशलता) छात्रों में है। अतः स्वरोजगार से बेहतर कोई अन्य विकल्प आत्मनिर्भरता हेतु हो ही नहीं सकता। कक्षा 6 से ही व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त होने पर छात्र भविष्य के प्रति आशंकित व भ्रमित न होकर आशावान व आत्मविश्वास से भरपूर होंगे। व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा इंटर्नशिप करके छात्र सफलता के नये क्षितिज को छुएंगे। विदेशों में भी इसी प्रकार की शिक्षा को अपनाया गया है। और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त किये गये हैं। अब हमारे छात्र इंटर, स्नातक, परास्नातक और पी0एच0डी0 करके बेरोजगार नहीं घूमेंगे बल्कि व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके दूसरों को रोजगार प्रदान करने वाले बन जायेंगे।

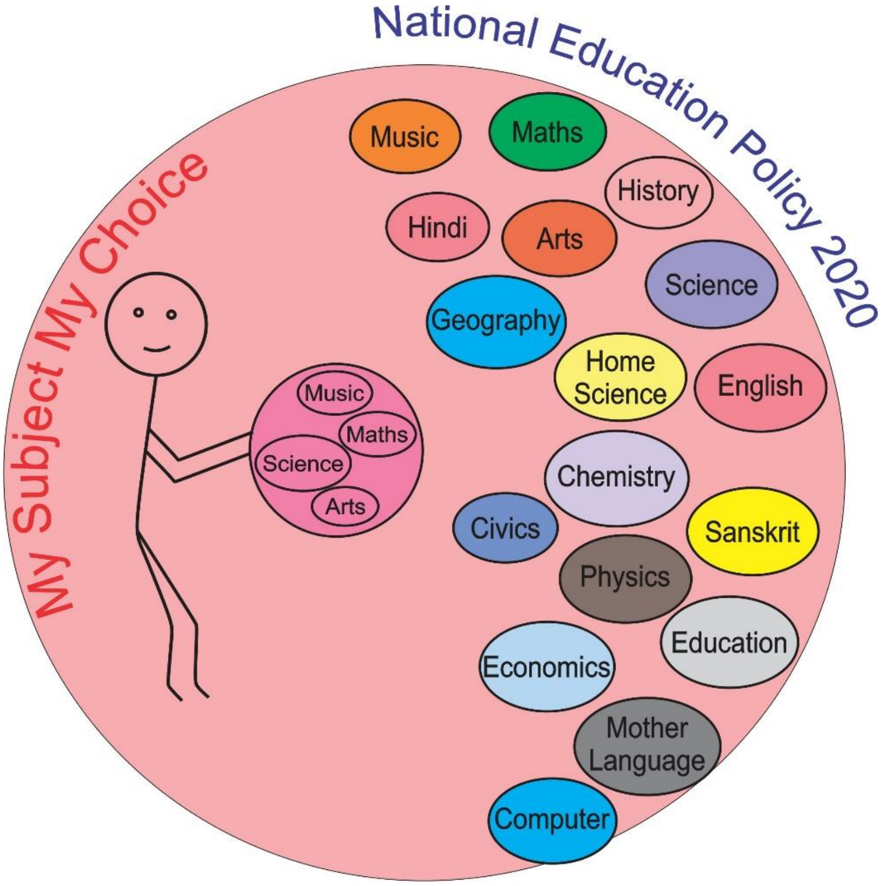


नवीं कक्षा से छात्रों को विषय चुनने की आजादी होगी। अब विषय कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि वर्गों में विभाजित नहीं होंगे। छात्र सभी विषयों में से अपनी पसंदके विषयों को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। संस्कृत के साथ गणित, विज्ञान, कला, गृह विज्ञान, वाणिज्य विषयों को अपनी रूचि के अनुसार चुन सकेंगे जिससे भविष्य की नयी सम्भावनाओं के द्वार खुलेंगे। गलत विषय का चुनाव करने के कारण कई बार छात्र अपने मनपसंद कार्यों व व्यवसाय के लिए आवश्यक योग्यता व अर्हता को प्राप्त करने में चूक जाते हैं। अपने साथियों की देखा–देखी गलत विषय चुनने के कारण छात्रों को कई बार पछताना ही पड़ता है। न तो वह विषय को समझ पाते हैं और न उसमें विशेष योग्यता ही हासिल कर पाते हैं। अब छात्रों के सामने कई व्यवसाय होगें जिनको वह अपनी पसंद के अनुसार चुन सकेंगे। शिक्षा को आज दीवारों और सीमाओं से मुक्त करने का संकल्प रा0शि0नी0 2020 द्वारा लिया गया है। छात्रों के अंदर विद्यमान गुणों व विशेषताओं को विकसित करने का पूरा मौका व वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालय एक उद्यान और छात्र इसके पौधे होंगे तथा शिक्षक माली की तरह उनके वृद्धि व विकास हेतु उचित वातावरण का निर्माण करेंगे। बुराइयों की खरपतवार को काटेंगे व समयानुसार खाद, पानी, रूपी ज्ञान व परामर्श प्रदान करेंगे। नई शिक्षा नीति के साथ शिक्षा के एक नये युग का सूत्रपात होगा जो विश्व में भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करेगा।

दसवीं बोर्ड को समाप्त करना उचित या अनुचित है इसके विषय में अनेक मत रहे हैं और रहेंगे। किन्तु 10वीं बोर्ड को लेकर छात्र/छात्राओं में बढ़ते तनाव, अवसाद, निराशा, कुंठा, आत्महत्या की प्रवृत्ति, घर से पलायन, नकल, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं को देखते हुए इसे अन्य स्कूली परीक्षाओं के समान ही गृहपरीक्षा बना देना मेरे विचार से सर्वथा उचित होगा। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और माता–पिता का अपने बच्चों से आवश्यकता से अधिक अपेक्षाएं रखना अन्य बच्चों से अंकों की तुलना छात्रों में तनाव व निराशा को जन्म देती है जो छात्र इस तनाव व कुंठा का सामना नहीं कर पाते हैं वह टूट जाते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि छात्र स्वअध्ययन पर जोर देने की बजाए कोचिंग संस्थान को अधिक अंक पाने का जरिया समझ बैठते हैं। और पूरी तरह से कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं स्वयं पर विश्वास खो देते हैं। शिक्षा नीति 2020 में छात्रों को इस दबाव व तनाव की अवस्था को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

**प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि** पढ़ाई से मिल रहे तनाव से अपने बच्चों को निकालना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि परीक्षा इस तरह होनी चाहिए कि छात्रों पर बेवजह का दबाव न पड़े। साथ ही यह भी कोशिश होनी चाहिए कि केवल एक परीक्षा से छात्रों का मूल्यांकन न किया जाए। बल्कि उनके विकास के अलग–अलग पहलुओं से जुड़ा मूल्यांकन हो। यही वजह है कि रा0शि0नी0 2020 में छात्रों को मार्कशीट की जगह उनके सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें छात्र की विशिष्ट क्षमता, योग्यता, रवैया, प्रतिभा, कौशल, क्षमता शामिल होगा।

**प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,** ''जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएंगे तो छात्र इस नए पाठ्यक्रम के साथ नए भविष्य की तरफ कदम बढ़ांएगे।'' यह पाठ्यक्रम दूरदर्शी, भविष्य निर्माण करने वाला और वैज्ञानिक होगा।

विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल तैयार करेंगे जैसे–वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएँ। परीक्षा में सुधार के साथ–साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में भी सुधार किया जायेगा। रा0शि0नी0 2020 के अनुसार छात्रों का मूल्यांकन तीन स्तरों पर होगा–

**प्रथम स्तर**–छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन करेंगे।

**द्वितीय स्तर**–सहपाठी, अपने साथी का मूल्यांकन करेंगे।

**तृतीय स्तर**–शिक्षक द्वारा मूल्यांकन

- बोर्ड परीक्षा में पूरा ध्यान ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि बच्चों की रटने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सके। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किये जाएेंगे। जैसे–साल में दो बार परीक्षाएँ कराना तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा तथा व्याख्यात्मक परीक्षा की दो श्रेणियों में विभाजित करना आदि।
- रा0शि0नी0 2020 की नयी स्कूली शिक्षा प्रणाली 5+3+3+4 के अनुसार छात्र अब कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर

पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हे उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा।

- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएगें। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में ''परख'' (PARAKH) नामक एक नए ''राष्ट्रीय आकलन केंद्र'' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए ''कृत्रिम बुद्धिमत्ता'' (Artificial Intelligence-AI) आधारित साफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। यह एक प्रकार का निर्देशन व परामर्श देने का कार्य करेगा। शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए ''कृत्रिम बुद्धिमत्ता'' एक कुशल, अनुभवी, विद्वान निर्देशनकर्ता की भूमिका का निर्वाह करेगी। विभिन्न आयोगों द्वारा विद्यालयों में छात्रों की समस्याओं को हल करने में सहायता व निर्देशन हेतु निर्देशन व परामर्शदाता की नियुक्ति करने का सुझाव दिया गया है किन्तु इतनी बड़ी संख्या में निर्देशनकर्ता/परामर्शदाता की नियुक्ति संभव नहीं हो सकी। रा0शि0नी0 2020 ने 'टेक्नोलॉजी' का उपयोग करके इस समस्या का सरल समाधान खोज लिया है।
- रा0शि0नी0 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली/विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा ''स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा'' (NCFSE-2020-21 National Curricular Frame Work for School Education) तैयार की जाएगी।

रा0शि0नी0 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आंकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आंकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

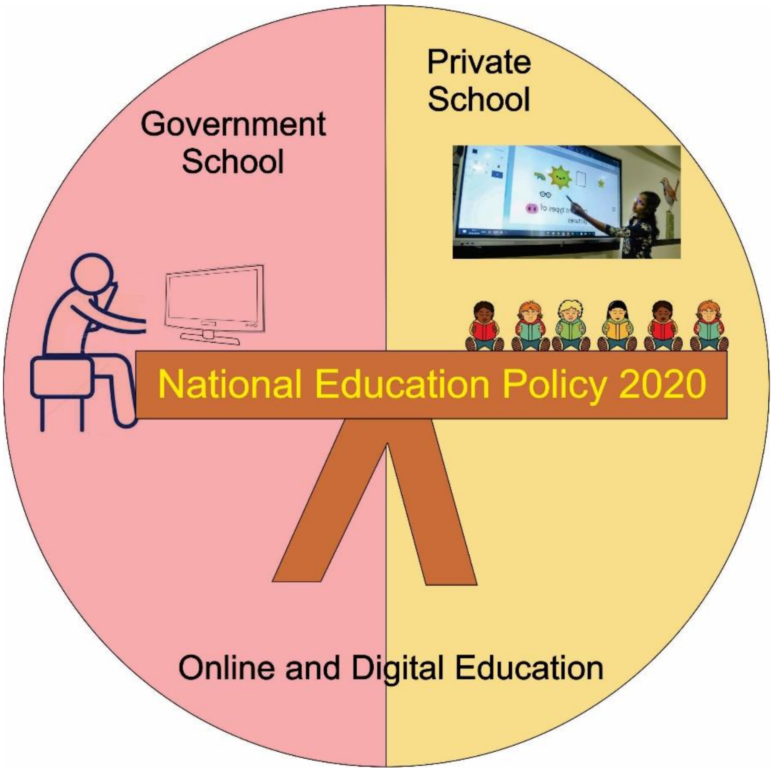


नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कम्प्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न एप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक, और सर्वसुलभ बनाने की बात कही गयी है। वर्तमान में 'कोरोना महामारी' के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कम्प्यूटर, लैपटॉप व मोबाइल द्वारा व मोबाइल एप द्वारा पढ़ाई आज की आवश्यकता बन चुकी है। ऑनलाइन शिक्षा, औपचारिक शिक्षा के सभी कार्यों को भली–भांति एवं सुचारू रूप से करने में महती भूमिका निभा रही है। इसमें पढ़ाई को अधिक रोचक बनाने के उपाय जैसे–रंगबिरंगे चित्र, चार्ट, पोस्टर, विडियो, क्रियात्मक मॉडल सभी उपलब्ध होते हैं जिसका समयानुसार एवं आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सकता है। औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सीमित व संकुचित होता है किन्तु ऑनलाइन शिक्षा द्वारा ज्ञान के असीमित भण्डार का लाभ उठाया जा सकता है। अधिकांश विद्यालयों में प्रयोगशालाएँ एवं पुस्तकालय का अभाव होता है जिसे ऑनलाइन या डिजिटल प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालय द्वारा दूर किया जा सकता है।

**माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी** ने प्रभावी ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ''शिक्षकों को खुद को अपग्रेड और अपडेट करना होगा। साथ ही बच्चों को उनकी रूचि के साथ सीखने के लिए प्रेरित करने की भी सलाह दी। डिजिटल माध्यम से पढ़ाई के जो भी साधन हैं उनकी पहुंच ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले हर वर्ग के बेटे–बेटियों तक हो।''

शिक्षकों को राष्ट्रनिर्माता बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ''अच्छे भवन, मंहगे उपकरण या सुविधाओं से

स्कूल नहीं बनता है बल्कि एक अच्छे स्कूल को बनाने में शिक्षको की निष्ठा और समर्पण ही निर्णायक सिद्ध होते हैं।''

आने वाले समय में शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में विषय सामाग्री/ पाठ्यसामग्री तैयार करना, वर्चुअल प्रयोगशाला, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस करने जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

ऑनलाइन शिक्षा ने विद्यालय/औपचारिक शिक्षा की कई समस्याओं को भी हल किया है। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाये पाठ को न समझने पर छात्र ऑनलाइन उपलब्ध किसी और विद्यालय के शिक्षक द्वारा बनाये विडियों से पढ़ाई कर सकता है। आज अधिकतम सरकारी विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनमें सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं ऐसे में छात्र को उन विषयों का ज्ञान देने के लिए विद्यालय प्रधानाचार्य अन्य विद्यालय के शिक्षकों का विडियो छात्रों को भेजकर शिक्षकों की कमी से होने वाली समस्या का समाधान कर रहे हैं। विद्यालयों में भी शिक्षकों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाई एक अच्छा उपाय हो सकती है। इसमें प्रोजेक्टर को मोबाइल/इंटरनेट से जोड़कर विभिन्न विषयों की पढ़ाई विद्यालय में कराई जा सकती है। साथ ही छात्र विषयवस्तु से संबंधित समस्या का ऑनलाइन समाधान भी उस शिक्षक से प्राप्त कर सकते हैं तथा विषय के नोट्स भी पीडीएफ फाइल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी विषय की पाठ्यपुस्तक को ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है इससे छात्रों के ज्ञान की वृद्धि होती है और समझ में अधिक आता है साथ ही छात्र विषय को आत्मसात कर पाते है अभ्यास भी कर सकते है इससे रटन्त विद्या का अन्त संभव है जो विषयवस्तु को समझे बिना केवल रटने पर जोर देती है। ऑनलाइन शिक्षा ने छात्रों के सामने ज्ञान के द्वार खोल दिये है आज ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा पूरा विश्व उनकी आँखों के सामने उपस्थित होता है जिससे ज्ञान का विस्तार आदान–प्रदान आसान हो गया है। आनलाइन शिक्षा वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण, उपयोगी, सरल विकल्प है।

**शिक्षा के उद्देश्य :**

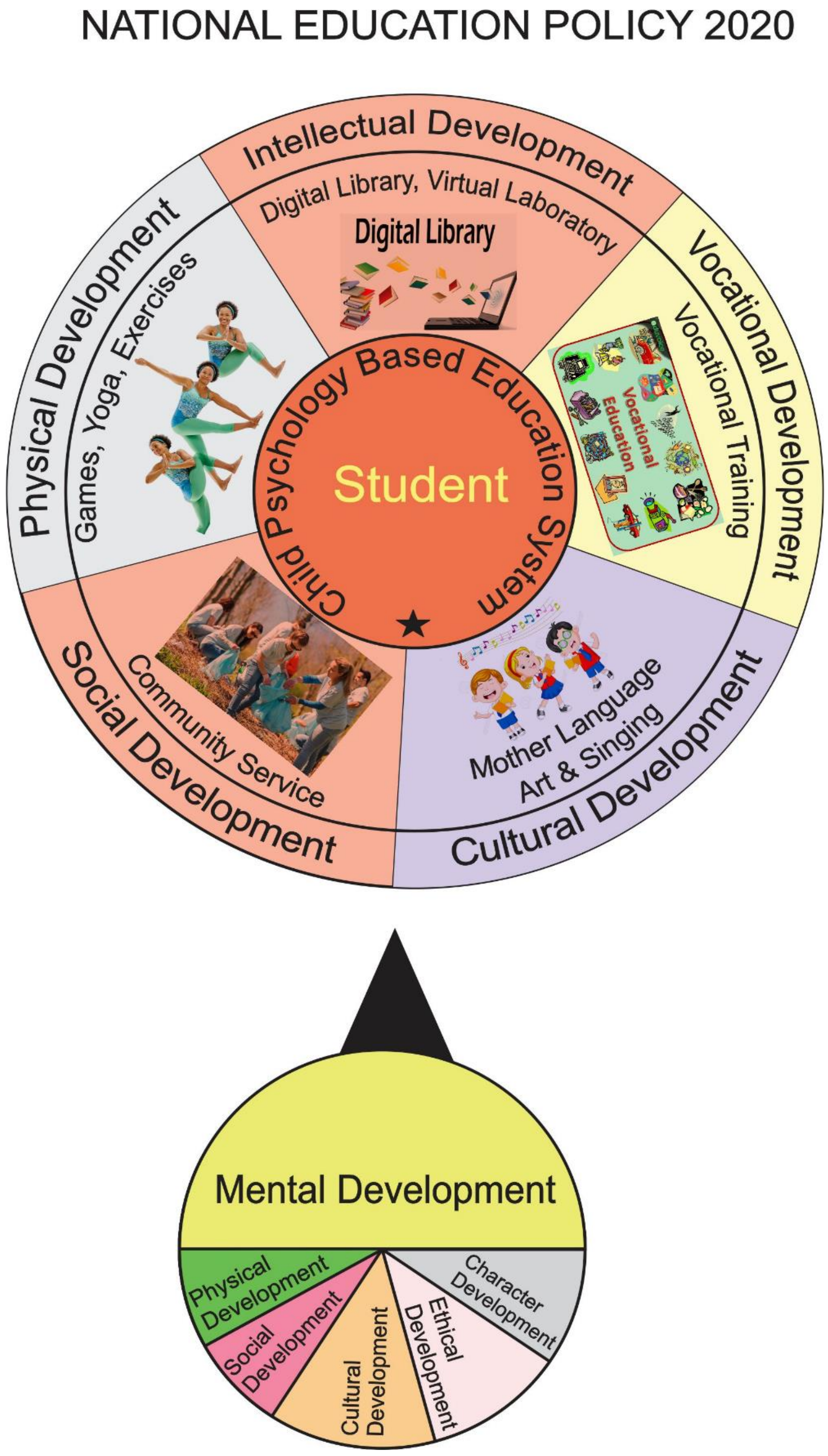
NATIONAL EDUCATION POLICY 2020
Intellectual Development
Digital Library, Virtual Laboratory
Digital Library
Vocational Development
Vocational Training
Vocational Education
Physical Development
Games, Yoga, Exercises
Child Psychology Based Education System
Student
Social Development
Community Service
Cultural Development
Mother Language
Art & Singing
Mental Development
Physical Development
Social Development
Cultural Development
Ethical Development
Character Development

शिक्षा एक सोद्देश्य प्रक्रिया है अतः शिक्षा प्रदान करने के पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक होता है। शिक्षा के उद्देश्य देश, काल व परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति सम्पूर्ण शैक्षिक व्यवस्था के द्वारा की जाती है।

बी0एम0ब्लूम महोदय के अनुसार, ''शैक्षिक उद्देश्य का अर्थ उन सुस्पष्ट रीतियों के निर्माण से है जिनके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन सम्भव होता है।'' अतः शैक्षिक प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक होता है।

शैक्षिक उद्देश्यों को हम एक इमारत की नींव के रूप में देख सकते हैं। यह उद्देश्य ही शिक्षा व्यवस्था को आकार और आधार प्रदान करते है जिसपर पूरी शिक्षा प्रक्रिया आधारित होती है। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति तथा आत्माभिव्यक्ति और मोक्ष की प्राप्ति था। इसी के आधार पर शिक्षा की संरचना को आकार दिया गया था। जो छात्रों को मोक्ष प्राप्ति अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलने का मार्ग बताती थी। वैदिक कालीन उद्देश्य के आधार पर ही विभिन्न विषयों अर्थात लौकिक तथा पारलौकिक का ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जाता था। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों द्वारा धर्म प्रचार को तथा सांसारिक सुखों की प्राप्ति को शिक्षा का उद्देश्य माना गया। अतः छात्रों में धार्मिक कट्टरता व सासांरिक सुखों के प्रति आसक्ति का विकास हुआ। ब्रिटिश काल में शिक्षा का उद्देश्य इसाई धर्म का प्रचार तथा अंग्रेजी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नौकर तैयार करना था। जो अंग्रेजी भाषा जानते हो अंग्रेजों की तरह वेषभूषा और विचारधारा हो। इसने एक अलग वर्ग को तैयार किया जो अंग्रेजी और अंग्रेजों का गुलाम था। आधुनिक शिक्षा या स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के उद्देश्यों का पुनः निर्धारण करने की आवश्यकता को महसूस किया गया। और राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1986 आदि के द्वारा समय–समय पर शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में अमूल्य सुझाव दिये गये। जिनमें से कुछ को कार्यान्वित किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में यदि बात की जाए तो हम देखते हैं कि इसमें शिक्षा के सर्वांगीण उद्देश्य को महत्व प्रदान किया गया है। इससे पहले भी शिक्षा के सर्वांगीण उद्देश्य को ही शिक्षा का उद्देश्य माना गया था किन्तु कार्यात्मक रूप में देखा जाए तो केवल मानसिक विकास के ईदगिर्द ही पूरी शिक्षा व्यवस्था घूमती दिखती है। मानसिक विकास को इतनी प्रमुखता प्रदान की गयी कि अन्य विकास यथा शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, गौण उद्देश्य बन कर रह गये। किन्तु रा0शि0नी0 2020 में सभी उद्देश्यों को समान रूप से महत्व देने का संकल्प है।

शारीरिक विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था में खेलकूद, योगा प्रातः व्यायाम को प्रमुखता दी गयी है। प्रातःकालीन सभा में प्रार्थना के साथ–साथ योगा और व्यायाम को प्रतिदिन कराना अनिवार्य है। साथ ही आत्मरक्षा के लिए छात्र/छात्राओं को जूडो–कराटे का प्रशिक्षण देना भी आवश्यक माना गया है। प्रत्येक विद्यालय में खेल का मैदान, खेलकूद की सामग्री तथा खेलकूद का समय–सारणी में स्थान भी आवश्यक रूप से शामिल किया गया है। जिससे सभी छात्र स्वास्थ्य लाभ के साथ–साथ अपनी रूचि के अनुसार खेल को खेल सकें। छात्रों के वैयक्तिक

विकास तथा देश के लिए योगा, व्यायाम, खेल का प्रशिक्षण लाभदायक है।

## स्नातक स्तर पर बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था

(Multiple Entry and Exit System) प्रारम्भ करने का निर्णय दूरगामी परिणाम देगा। शिक्षा व्यवस्था लचीली बन जाएगी और सही अर्थों में बालक या छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार ढल जाएगी। समय एवं आवश्यकतानुसार छात्र किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे और परिस्थितिनुसार छोड़ भी सकेंगे। किन्तु पहले की तरह अब धन, समय व परिश्रम की हानि नहीं होगी। रा0शि0नी0 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे→स्नातक स्तर पर एक वर्ष पढ़ाई करने के बाद–सर्टिफिकेट

→स्नातक स्तर पर 2 वर्ष पढ़ाई करने के बाद–एडवांस डिप्लोमा

→स्नातक स्तर पर 3 वर्ष पढ़ाई करने के बाद–स्नातक की डिग्री

→स्नातक स्तर पर 4 वर्ष पढ़ाई करने के बाद–शोध के साथ स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी।

- रा0शि0नी0 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में ''सकल नामांकन अनुपात'' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3 प्रतिशत (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक 'एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, जिससे अलग–अलग संस्थाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
- रा0शि0नी0 2020 में एम0फिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है।
- चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India-HECI) का गठन किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा आयोग के कार्यो के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है–

➢ **विनिमय हेतु :** राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council-NHERC)

➢ **मानक निर्धारणः** सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council G.E.C.)

➢ **वित्त पोषणः** उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council-HEGC)

➢ **प्रत्यायनः** राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council - NAC)

- महाविद्यालयों की सम्बद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

- देश में आई आई टी (I.I.T) और आई आई एम (I.I.M.) के समकक्ष वैश्विक मानको के ''बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (Multidisciplinary Education and Research Universities- MERU) की स्थापना की जाएगी।
- शिक्षा, मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान–प्रदान हेतु 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (National Education Technology Forum-NETF) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी।

**शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार :**

नई शिक्षा नीति में अध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को उन्नत बनाने हेतु पाठ्यचर्या में व्यापक बदलाव किये जायेंगे। शिक्षकों की पदोन्नति अब समय–समय किये गये कार्यों के आंकलन के आधार पर ही होगी। इससे शिक्षकों की अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। शिक्षण–प्रक्रिया में सुधार होगा। छात्रों का सम्प्राप्ति स्तर बढ़ेगा। सरकारी स्कूलों के शिक्षक विद्यालय में अनावश्यक कार्यों पर समय व्यतीत करने की बजाय अध्यापन कार्य तथा छात्रों की समस्याओं को हल करने में अमूल्य योगदान देंगे। इससे उन शिक्षकों का भी सम्मान बढ़ेगा जो अपने कार्यों को सदैव ईमानदारी से व परिश्रम से पूरा करने में लगे रहते हैं स्वयं की उन्नति के साथ–साथ विद्यार्थियों को भी प्रेरित करते रहते हैं। इस सुधार के द्वारा पदोन्नति सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को मिलेगी जो इस कसौटी पर खरा उतरेंगे। रा0शि0नी0 2020 के अनुसार शिक्षकों को बेहतर और प्रभावशाली शिक्षण हेतु प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे अनेक लाभ होंगे–शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकेंगे, अपनी कमियों को जानकर उसमें यथासंभव सुधार करेंगे, छात्र की रूचि, आवश्यकता व बुद्धि के अनुसार शिक्षण करेंगे। पढ़ाने से पहले छात्रों को प्रेरित करेंगे, सीखने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से छात्र तत्पर होंगे, छात्रों में विषयवस्तु की समझ बढ़ेगी, शिक्षण कार्य में नवीनता आयेगी। घिसी–पिटी परिपाटी से शिक्षण कार्य बोझिल व उबाऊ हो जाता है। शिक्षण में नवीन तकनीकी जैसे–प्रोजेक्टर, मॉडल, क्रियात्मक मॉडल, कम्प्यूटर, मोबाइल का प्रयोग करना सीखेंगे जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। छात्रों को कक्षा में विषयवस्तु पूरी तरह से समझ में आ जाएगी तो उसे ट्यूशन और कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छात्र स्वाध्याय में रूचि लेंगे। छात्रों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि होगी, ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों का विकास होगा। अध्यापक कक्षा में रूचि लेंगे तो छात्र भी पूरे मनोयोग से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने शिक्षण में सुधार हेतु शिक्षक प्रयासरत रहेंगे और छात्रों की शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगें। अध्यापक और छात्र का संबंध पिता–पुत्र की भांति (वैदिक कालानुसार) मधुर बनेंगे। शिक्षकों का सम्मान बढ़ेगा। अध्यापक अपने ज्ञान को अद्यतन करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा (NCERT) के परामर्श के आधार पर ''अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curricular Framework for Teacher Education NCFTE 2021) का विकास किया जाएगा।

**अध्यापक शिक्षा में सुधारः**

अध्यापक शिक्षा की पाठयचर्या (Curriculum) में बदलाव के जरिए अध्यापक शिक्षा को उन्नत बनाने का प्रयास होगा। देश व समाज के भावी नागरिकों, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी आदि का विकास शिक्षक के कंधों पर ही होता है। यदि शिक्षक स्वयं शिक्षण कार्य के प्रति समर्पित होंगे और उच्च तकनीक का प्रयोग का सीखेंगे तो शिक्षक, शिक्षार्थी तथा समाज और देश का सर्वतोमुखी विकास होना निश्चित है। पाठ्यचर्या को यथासंभव क्रिया आधारित बनाया जाना चाहिए अर्थात भावी शिक्षकों को या छात्राध्यापकों को अधिक से अधिक शिक्षण का अभ्यास करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अध्यापक शिक्षा के संस्थानों में सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास कराया जाता है किन्तु उसमें वास्तविकता कम व नाटकीयता अधिक होती है। अतः स्वाभाविक वातावरण अर्थात विद्यालय में ही भावी शिक्षकों को शिक्षण का अभ्यास करने का अधिक समय व अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान विद्यालय में शिक्षण का अभ्यास कराने में रूचि नहीं लेते है और भावी शिक्षकगण भी इस परिश्रम से बचने का प्रयास करते हैं यह दशा अत्यंत ही शोचनीय है जिसमें सुधार होने की उम्मीद रा0शि0नी0 2020 में जगाई है।

**4 वर्षीय एकीकृत बी0एड0 डिग्री :**

रा0शि0नी0 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी0एड्0 डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। चार वर्षीय एकीकृत बी0एड्0 डिग्री का अर्थ है स्नातक की डिग्री + बी0एड्0 डिग्री यानि चार वर्षीय स्नातक की पढ़ाई के साथ छात्र बी0एड्0 की पढ़ाई भी करेंगे। और विद्यालय में शिक्षण का अभ्यास भी इसी में शामिल होगा। अध्यापन के लिए इसे न्यूनतम डिग्री योग्यता बना दिये जाने पर जो बालक या बालिका अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं वह इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्यापन कार्य को सीख सकेंगे। वर्तमान में 3 वर्षीय स्नातक करने के बाद छात्र यहाँ–वहाँ भटकते रहते हैं बी0एड0 में प्रवेश के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा देते है। इस सब में समय व धन की बहुत हानि होती हे। चार वर्षीय एकीकृत बी0एड्0 डिग्री कार्यक्रम के आरम्भ होने पर छात्र एक ही बार प्रवेश परीक्षा देकर चार वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करके अध्यापक बनके बाहर आयेंगे जिससे समय और धन की बचत होगी। छात्र निरूद्देश्य भटकने की बजाय कम समय में रोजगार प्राप्त करके स्वावलंबी बन सकेंगे।

## नई शिक्षा नीति में नवाचार के सुझाव

- **बर्थडे गार्डन :** छात्र/छात्रा के जन्मदिन पर विद्यालय परिसर में औषधीय पौधा रोपना और उसका संरक्षण करना।
- **ट्राइबल म्यूजियमः** प्रचलन से बाहर वस्तुओं का संग्रह कर विद्यालय में संग्रहालय बनाना।
- **भाषण कला :** अक्षर ज्ञान तथा 2 मिनट में ज्यादा बोलने वाले (अधिक शब्द भण्डार, धारा प्रवाह बोलना) छात्र/छात्रा को इनाम देना, प्रोत्साहित करना।

- **अतिरिक्त कक्षा शिक्षण :** कमजोर बच्चों को विद्यालय शुरू होने के पहले आधा घंटा अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना।
- **वर्चुअल रियेलिटी बॉक्सः स्टॉम्प किट तैयार करना–**
    - कक्षा 1 का छात्र A लिखता, कक्षा 2 का छात्र Apple
    - कक्षा 3 का छात्र Apple वाक्य लिखता है।
- **वाचन :** प्रतिदिन एक पीरियड लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ने के लिए ही निर्धारित करना।
- **कबाड़ से जुगाड़ः** कबाड़ की वस्तुओं से गणित, विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला के मॉडल बनाना।
- **विज्ञान किट :** विज्ञान के हर पाठ के साथ दिये गये क्रियाकलाप को करने के लिए एक ''विज्ञान प्रायोगिक किट'' तैयार करना। जिसमें प्रयोग के लिए आवश्यक समस्त सामग्री रखी जाय। विज्ञान शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाय तथा कार्यशाला का आयोजन किया जाय।
- **मोबाइल शिक्षा :** कठिन विषयों या प्रकरणों को समझाने के लिए उसका विडियो, बनाकर मोबाइल पर भेजा जाय। जिससे कमजोर छात्र उसे बार–बार देख सकें सीखने का अभ्यास कर सकें।
- **I.C.T. का प्रयोग (Information & Communication Technology)**

विद्यालय में प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर का प्रयोग करके कठिन विषयों को मनोरंजन तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए।

- **दोस्ती क्लब / मित्रता क्लब :** छात्र / छात्राओं की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जानने, समझने तथा उनके समाधान के लिए दोस्ती क्लब बनाया जाये। शिक्षक तथा छात्र मित्रता से शिक्षक, छात्र की समस्याओं को जानकर हल करने का प्रयास करें।
- **समानता की भावना :** विद्यालय में जाति तथा धर्म आधारित भेदभाव की ऊँच– नीच की भावना को समाप्त करके समानता का भाव विकसित करने हेतु, संविधान की प्रस्तावना को विद्यालय की दीवार पर लिखा जाय। इस पर वार्तालाप का आयोजन किया जायं नुक्कड़ नाटक तथा रोल प्ले विधि द्वारा ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करके समानता का भाव विकसित किया जाय। सामूहिक व सामाजिक कार्य कराये जायें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देर में भले आयी हो लेकिन इसका कार्यक्रम, योजना, कार्यविधि इतनी प्रभावशाली है कि यह पिछली सभी शिक्षा योजनाओं की कमियों को दूर कर देगी। यदि नई शिक्षा योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया तो भारत निश्चित रूप से विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा दिखाई देगा। नई शिक्षा नीति 2020 वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा प्रणाली में सुधार की एक व्यापक, विस्तृत कार्ययोजना है। इस शिक्षा नीति के द्वारा हम छात्रों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का सफल प्रयास कर सकेंगे।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


1. wikipedia.com (National Education Policy 2020)
2. www.google.com
3. www.m.livehindistan.com
4. wwww.jagran.com
5. wwww.naidunia.com
6. Hindustan, New National Educational Policy 2020